सान्ध्य हिन्दी दैनिक | जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 14 | जौनपुर, शनिवार, 31 अगस्त 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में जमीनी हालात का जायजा लिया

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में हाल में भारी बारिश के बाद शुक्रवार को अपने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के जमीनी हालात का जायजा और प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। अहमदाबाद के कई हिस्से, जो शाह की गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, इस सप्ताह की शुरुआत में भारी बारिश के बाद घुटनों तक पानी में डूब गए थे। भाजपा की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ''मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए शाह ने सामान्य जन–जीवन बहाल करने, बीमारियों की रोकथाम करने और नागरिकों के सामने आ रही समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही शाह ने अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जिलों के कलेक्टर और नगर निगम आयुक्तों से फोन पर चर्चा की। विज्ञप्ति के अनुसार, ''उन्होंने अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और उन्हें बारिश के पानी की निकासी में तेजी लाने तथा सड़कों और नालों की सफाई युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए, ताकि सामान्य जन–जीवन बहाल हो सके। सफाई के अलावा शाह ने अधिकारियों से बारिश के बाद बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तुरंत फॉगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव शुरू करने को भी कहा।

यूपी के लिए कांग्रेस का पीएमडी दांव

लखनऊ, संवाददाता। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, मुस्लिम और दलित (पीएमडी) दांव चला है। यहां के तीन वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय कमेटी में शामिल करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खास माने जाने वाले शाहनवाज आलम और सुशील पासी को राष्ट्रीय सचिव बनाते हुए बिहार का सह प्रभारी बनाया है। इसी तरह गुर्जर समाज से आने वाले विदित चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर हिमाचल व चंडीगढ़ का सह प्रभारी बनाया है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में लगातार सामाजिक न्याय को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आर. एन. आई द्वारा लगाई गई आपत्ति के क्रम में वर्ष 01 अंक 01 का पुनः प्रकाशन किया गया था, जिसके कारण वर्ष एवं अंक में त्रुटि हो गई थी। जिसे आज दिनांक से सही कर दिया गया है।

संपादक
दैनिक देश की उपासना

प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा, वधावन बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर का दौरा करेंगे। वह सुबह 11 बजे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे, जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद, दोपहर 1.30 बजे वह पालघर के सीआईडीसीओ मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पालघर में पीएम मोदी वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपये है। वधावन पोर्ट गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा जहां बड़े कंटेनर जहाजों का आवागमन संभव होगा। वधावन पोर्ट पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे ट्रांजिट समय और लागत को कम किया जा सकेगा। इस पोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें गहरे बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं, और आधुनिक पोर्ट प्रबंधन प्रणाली शामिल होगी। इस परियोजना से स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बल मिलेगा। वधावन पोर्ट परियोजना

में सतत विकास प्रथाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने और कठोर पारिस्थितिकी मानकों का पालन करने पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 1,560 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं देश भर में मत्स्य पालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को मजबूत करने के लिए होंगी। इन पहलों से मत्स्य पालन क्षेत्र में पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर जहाजों के लिए संचार और समर्थन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे, जिसका बजट लगभग 360 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत, 13 तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक लाख ट्रांसपोंडरों को चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। यह संचार प्रणाली इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है, जो समुद्र में गए मछुआरों को द्विपक्षीय संचार स्थापित करने में मदद करेगी और बचाव ऑपरेशनों के साथ–साथ मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। प्रधानमंत्री अन्य पहलों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें मछली पकड़ने के हार्बर और एकीकृत एक्वा पार्क का विकास शामिल है। साथ ही, मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जाएगा। ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में लागू की जाएंगी और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, मछली पकड़ने से बाद उनके प्रबंधन में सुधार करने, और मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल लाखों लोगों के लिए सतत आजीविका प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण ढांचे और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करेंगी।

प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मत्स्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें मछली पकड़ने के लिए हार्बर और मछली बाजारों का विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में लगभग 800 वक्ता 350 से अधिक सत्रों को संबोधित करेंगे। इनमें नीति निर्माता, नियामक, वरिष्ठ बैंकर, उद्योग प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे।

सारे अरोप बेबुनियाद, सरकार जांच के लिए तैयार – सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश, एजेंसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के नेता विपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर के आरोपों का खंडन किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने घर के ऊपर एक ड्रोन देखा और राज्य सरकार पर गोपनीयता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सुक्खू ने कहा कि अगर ऐसी गतिविधियां होती हैं तो सरकार जांच के लिए तैयार है। हम उसके घर के ऊपर ड्रोन क्यों उड़ाएंगे? वह पूर्व सीएम थे। मैंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया है कि अगर ऐसी चीजें हुई हैं, तो हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन वह इसे मुद्दा बना रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सुक्खू ने कहा कि वह केंद्रीय एजेंसियों से भी इस बात को पूछ लेंगे कि कहीं ईडी और सीबीआई तो यह जासूसी नहीं करवा रही। वे इसके लिए दोनों केंद्रीय एजेंसी को पत्र भी लिखेंगे। इससे पहले दिन में, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के लिए निकलते समय उन्होंने अपने घर के ऊपर एक ड्रोन देखा। उन्होंने सरकार पर पहले से ही फोन टैप करने और अब निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मैं विधानसभा के लिए निकल रहा था तो मैंने अपने घर के ऊपर एक ड्रोन देखा। यह सरकार निजता का उल्लंघन कर रही है। फोन पहले से ही टैप किए जा रहे हैं, और अब निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम को इस पर जवाब देना चाहिए था लेकिन वह इस पर चुप रहे।

बंगाल के संवेदनशील मुद्दे पर पीएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली – ममता

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने पहले भी बलात्कार के मामलों के लिए कड़े केंद्रीय कानून और अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पत्र में बनर्जी ने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट POCSO अदालतों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित अदालतें पूरे राज्य में पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर काम कर रही हैं।

भारत शिक्षा को दुनिया के साथ अधिक सहयोग बढ़ाने के प्रमुख माध्यम के रूप में देखता – एस. जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत आज शिक्षा को देश और दुनिया के बीच अधिक सहयोग बढ़ाने के एक ''प्रमुख माध्यम'' के रूप में देखता है। उन्होंने साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय को आशय पत्र सौंपने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में यह बात कही। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''आज हम भारत में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देख रहे हैं। यहां सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला परिसर स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''आज का कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों का भी प्रमाण है, जिसमें शिक्षा विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस प्रगति के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है।'' मंत्री ने कहा कि यह महज एक नीति नहीं है, बल्कि यह वास्तव में भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है, जो ''हमारे मानकों को उच्चतम वैश्विक स्तर तक बढ़ाने की आकांक्षा रखता है। जयशंकर ने कहा, इसका उद्देश्य भारत को उत्कृष्टता का केंद्र बनाना, दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करना, विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना करना और हमारे छात्रों और संकायों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना है।'' मंत्री ने कहा, ''आज हम शिक्षा को भारत और विश्व के बीच अधिक गहन सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखते हैं।

लोकतंत्र के गुणात्मक परिवर्तन के लिए विश्वसनीय मीडिया महत्वपूर्ण – गडकरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के लोकतंत्र और सामाजिक– आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन के लिए विश्वसनीय मीडिया महत्वपूर्ण है।

गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर राजनेता मीडिया के समर्थन की उम्मीद करता है, लेकिन मीडिया को लोकतंत्र और देश के लिए जो अच्छा है उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परनिर्भर थे, लेकिन अब वे सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मीडिया में हमें विश्वसनीयता और सद्भावना की आवश्यकता है। लोग मीडिया से ऐसी जानकारी की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि वे हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन ला सकें। उन्होंने कहा, "सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हम सबका अंतिम लक्ष्य है, इसलिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब हर कोई जानकारी को समझने में दिलचस्पी रखता है।

गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उनका सपना भारत को 'आत्मनिर्भर' और 'पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था' बनाने का है। उन्होंने कहा कि रोजगार की संभावनाएं पैदा करना भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बुनियादी समस्या है। गडकरी ने कहा, "हमें रोजगार पैदा करने के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत है।

राजनीतिक एजेंडा हमारे बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर हावी नहीं होना चाहिए - शिक्षा मंत्री प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजनीतिक एजेंडा हमारे बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर हावी नहीं होना चाहिए। पीएम श्री योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखा। प्रधान ने कहा, मैं सीएम स्टालिन से आग्रह करता हूं कि वे राजनीतिक मतभेदों के बजाय हमारे बच्चों के विश्व स्तरीय शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता दें। इससे कम कुछ भी हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। प्रधान ने स्टालिन को लिखे पत्र में कहा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तमिलनाडु सरकार ने 15 मार्च को शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में पीएम श्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा जताई थी। इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तमिलनाडु को एक मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा था। हालांकि, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राज्य ने एक संशोधित समझौता ज्ञापन के साथ जवाब में

नई शिक्षा नीति, 2020 के संपूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख करने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा दिया गया है। प्रधान ने पत्र में कहा, मोदी सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी की शिक्षा के माध्यम से भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है। यह नीति समावेशी शिक्षा और गतिशील शिक्षण वातावरण को प्राथमिकता देती है, जिसे केंद्र और तमिलनाडु दोनों सरकारों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, जिस तरह राज्य एनईपी, 2020 के साथ संरेखित समग्र शिक्षा योजना को लागू कर रहा है, उसी तरह यह उचित होगा।

कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चला रही बीजेपी – सिद्धारमैया

कर्नाटक, एजेंसी। कर्नाटक में जारी सिसायी वार–पलटवार के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा दावा किया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है।

उन्होंने कहा कि विधायक रविकुमार गौड़ा ने मुझे बताया कि भाजपा हमारे विधायकों को 100 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है। ऑपरेशन लोटस के जरिए ही बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आई थी। वे कभी भी जनता के आशीर्वाद से सत्ता में नहीं आये। 2008 और 2019 में वे ऑपरेशन लोटस और बैकडोर एंट्री के जरिए सत्ता में आए। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी–जेडी(एस) ऑपरेशन लोटस के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। राज्य में बीजेपी कभी भी लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 136 विधायकों की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना आसान बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कल राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और एमएलसी राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, शशिकला जोले, जनार्दन रेड्डी निरानी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का आग्रह करेंगे। भाजपा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन 'घोटाले' के सिलसिले में सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है।

जमात-ए-इस्लामी के पक्ष में खड़ीं हुई मबबूबा मुफ्ती

जम्मू–कश्मीर, एजेंसी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने जमात–ए–इस्लामी के लिए चुनाव ने चुनाव में भाग लेने की कोशिश की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई तीसरी ताकत उभरे। उन्होंने कहा कि पहले उनके लिए

को हराम बना दिया था। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, महबूबा ने कहा कि 1987 में, जब जमात–ए–इस्लामी और अन्य समूहों चुनाव हराम था, अब हलाल हो गया है। लेकिन पूरी तरह से, यह उनका फैसला है। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर जमात–ए–इस्लामी चुनाव लड़ना चाहती है तो यह अच्छी बात है। सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए, उनकी सभी संस्थाएं, संपत्तियां जो आपने फ्रीज की हैं, जब्त की हैं, उन्हें डी–फ्रोजन किया जाना चाहिए, उन्हें वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सत्ता मिलती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव हलाल हो जाता है और जब सत्ता चली जाती है तो चुनाव उनके लिए हराम हो जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों के साथ ष्हलाल और हरामष की इस प्रणाली की शुरुआत की। महबूबा ने कहा कि 1947 में, जब स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला पहली बार जम्मू–कश्मीर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने और बाद में भारत में शामिल हो गए, तब चुनाव हलाल थे। जब वे मुख्यमंत्री बने तो चुनाव हलाल थे। लेकिन जब उन्हें पद से हटा दिया गया, तो 22 साल के लिए चुनाव हराम हो गये। महबूबा ने यह भी कहा कि उन 22 सालों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि 1975 में, जब शेख अब्दुल्ला सत्ता में लौटे, तो चुनाव अचानक फिर से हलाल हो गए। महबूबा ने कहा कि चुनावों को हलाल या हराम बताने की यह व्यवस्था जारी है, जिससे जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ष्यह देखकर दुख होता है कि आज भी इस कथा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने सरकार से जमात–ए–इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने और उनकी जब्त की गई संपत्ति वापस करने का भी आह्वान किया।

भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन

झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले शिवराज ने कहा कि चंपई सोरेन भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक संपत्ति हैं। वह ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने का काम किया और उसी का नतीजा है कि उनकी जासूसी शुरू कर दी गयी है। भाजपा नेता ने कहा कि चंपई सोरेन का अपमान किया गया, यह सिर्फ चंपई सोरेन का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का अपमान है। उन्होंने आज भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है और हम उनका स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से यहां बीजेपी को मजबूती मिलेगी। चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। इससे पहले चंपई

सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह पार्टी की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से व्यथित होकर यह कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। चंपई सोरेन ने कहा, आज मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैं झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई जारी रखूंगा। पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को लिखे पत्र में वरिष्ठ आदिवासी नेता ने कहा कि झामुमो की वर्तमान कार्यशैली से व्यथित होकर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

संपादकीय

त्वरित परिणाम के नुकसान

हाल ही में, अनुबंध पर वरिष्ठ और मध्यम स्तर के सिविल सेवकों के रूप में 45 विशेषज्ञों को शामिल करने के जल्दबाजी में किए गए प्रयास और पहले के कृषि सुधार कानून, जिसे 2020 में बिना किसी बहस के जल्दबाजी में लागू किया गया और फिर एक साल बाद वापस ले लिया गया, दोनों ही सरकार की सुधार रणनीति में तीन सामान्य, कमजोर बिंदुओं की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले, सुधारों के रिपोर्ट कार्ड के लिए त्वरित जीत हासिल करना सामाजिक समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दरकिनार कर देता है। दूसरा, प्रमुख हितधारकों – क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग, जिसे संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत केंद्र सरकार की भर्ती का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया है, और कृषि के मामले में किसानों – से गहन सहमति के बिना जल्दबाजी में तैयार किए गए कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। तीसरा, निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए मंत्रालयों में नौकरशाही के लिए अवसरों के सिकुड़ने से जमीनी स्तर पर फीडबैक सूख गया। दोनों प्रस्तावों में खूबियाँ थीं। नौकरशाही के मुख्य कार्यों को करने के लिए महंगे, अल्पकालिक सलाहकारों को नियुक्त करने के बजाय नौकरशाही के भीतर कौशल को बढ़ाना और कृषि में बाजार की ताकतों को कम उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुक्त करना, योग्य उद्देश्य हैं। विडंबना यह है कि सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश का मामला 1952 में ही तय हो गया था, जब अखिल भारतीय सेवाओं को औपचारिक रूप दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा तथा कर, रेलवे और भारतीय विदेश सेवा जैसी केंद्र सरकार की "ग्रुप ए" केंद्रीय सेवाएँ सभी प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल करती हैं, उन्हें नेता बनने के लिए प्रशिक्षित करती हैं और उन्हें प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों में उच्च स्तर पर सिविल सेवकों के व्यापक आधार में शामिल करती हैं, जो आम तौर पर अन्य जूनियर कैडर से आठ सेवा वर्ष आगे होते हैं, जो यूपीएससी द्वारा नियुक्त लोगों को "पार्श्व" प्रवेशकर्ता के रूप में नापसंद करते हैं। आज, "पार्श्व प्रवेश" का अर्थ मौजूदा सरकारी कैडर के बाहर भर्ती करना है। अत्यधिक विशिष्ट पदों के लिए तैयार की गई एक प्रणाली, जिसे किसी भी मौजूदा कैडर से प्रतिनियुक्ति द्वारा नहीं भरा जा सकता है, लेकिन आरक्षण समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए इसका उपहास किया जाता है। 500 अधिकारियों वाले भारतीय आर्थिक सेवा के मामले पर विचार करें, जो 1967 से केंद्र सरकार का एक विशेष कैडर है। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार के सर्वोच्च पद पर कभी भी इससे कोई नहीं बैठा। इसके बजाय, इसे हमेशा पार्श्विक रूप से भरा जाता है। इससे यह भी मदद मिली कि चुने गए लोगों की साख बेदाग थी। डॉ. मनमोहन सिंह ऐसे ही एक व्यक्ति थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने – एक ऐसी उपलब्धि जिसकी बराबरी कोई अन्य सिविल सेवक नहीं कर सका। इस तंत्र का उपयोग बीएसईएस के पूर्व सीईओ आर.वी. शाही जैसे टेक्नोक्रेट को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सचिव, ऊर्जा के रूप में नियुक्त करने के लिए भी किया गया था। निजी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता से बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी। अब तक, प्रशासनिक चतुराई के कारण पार्श्विक प्रवेश को एक समय में कुछ अनूठे पदों तक सीमित रखा जाता था। इसने रोजगार में समान अवसर (एससीएसटीओबीसी के लिए नौकरी आरक्षण) के लिए संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 16) को कमजोर करने पर आरक्षण समर्थक कार्यकर्ताओं की नाराजगी को शांत किया। पिछली सफल पार्श्व नियुक्तियों और हाल ही में विफल प्रयास के बीच मुख्य अंतर यह है कि इसका उपयोग बल्क लेटरल हायरिंग के लिए किया जाता है। इसने नरेंद्र मोदी प्रशासन को नौकरी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बढ़ते आंदोलन के संभावित खतरे के प्रति उजागर कर दिया, जो कि जून 1990 में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के निर्णय से शुरू हुआ था। बल्क लेटरल एंट्री, तेजी से बढ़ते, महंगे, अल्पकालिक, निजी सलाहकारों को इन–हाउस विशेषज्ञता से बदलने का एक कुशल तरीका है। ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण सिद्धांत को लागू न करना फायदे से ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि यह भविष्य में सरकारी नियुक्तियों के तरीके को बदनाम करता है। मानव संसाधन प्रबंधन की मौजूदा कैडर प्रणाली गैर–योग्यतावादी अभिजात्यवाद से भरी हुई है। अधिकांश जूनियर कैडर (ग्रुप सी और बी सेवाएं) के पास करियर में प्रगति के सीमित अवसर हैं। इसके विपरीत, ग्रुप ए कैडर में, प्रोमोशन पद (कार्यभार द्वारा उचित नहीं) मौजूद हैं, जो पूरे बैच के लिए समयबद्ध पदोन्नति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह भी विचार करें कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए, नौकरी में आरक्षण नियुक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है, भले ही संविधान का अनुच्छेद 16 (14।) पदोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं लगाता है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के परिणामों में से एक यह है कि उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के बार–बार प्रयास करने के बाद अधिक उम्र में सरकार में शामिल होते हैं। ऐसे अधिकारी पहले भी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे शीर्ष पर विविधता (एससी, एसटी, ओबीसी प्रतिनिधित्व) संभावित रूप से कम हो जाती है। यह स्पष्ट है कि विशेष पार्श्व प्रविष्टि की आवश्यकता मुख्य रूप से आईएएस और प्रांतीय सिविल सेवाओं जैसे सामान्यीकृत कैडर की अपर्याप्तता से उत्पन्न होती है।

आत्मचिंतन या राजनीति को सामान्य रूप में चलना

आदित्य

अगर यह और कुछ नहीं दिखाता है, तो कलकत्ता, क्षमा करें, कोलकाता, जैसा कि पश्चिम बंगाल के आक्रामक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया है, मैं एक चौंकाने वाले क्रूर बलात्कार और हत्या पर हंगामा दर्शाता है कि शहर मरने से बहुत दूर है, जैसा कि राजीव गांधी ने कभी सोचा था। यदि मृत्यु वास्तव में सामने आती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी इंद्रियाँ जो मनुष्य को जानवरों से श्रेष्ठ बनाती हैं, वे मुरझा रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी को इसे नष्ट करने के लिए किसी भाजपाई चाल की आवश्यकता नहीं है। इसके अपने निवासियों का लालच, अश्लीलता और क्रूरता इसे बहुत अच्छी तरह से कर रही है, धन्यवाद। मनुष्य की कहानी में अपने अंतिम बोधगम्य योगदान में, एक विशाल 979–पृष्ठ संस्मरण, तेरा हाथ, महान अराजकता! भारतः 1921–1952, नीरद सी. चौधरी ने कलकत्ता निगम की तुलना की, जो भ्रष्टाचार और अक्षमता का एक गड्ढा था, जहाँ उन्होंने कभी काम किया था, स्वतंत्र भारत के साथ। उन्होंने लिखा, मैंने अनुमान लगाया था कि भारतीयों को राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित करने से भारतीय लोग एक कपटी शोषण के शिकार बन जाएँगे, जो उनके कष्टों के लंबे इतिहास में भी अद्वितीय है।" मैं इस विचार का विरोधी हो गया, और अपने आप से कहा कि इस घटना में भारत कलकत्ता नगर निगम बन जाएगा।" अगर कुछ है, तो यह वास्तव में बदतर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषिक्त उत्तराधिकारी, और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के अनुसार, प्रतिदिन 90 बलात्कारों की रिपोर्ट, हर घंटे चार और हर 15 मिनट में एक" के लिए अपमानित नगरपालिका भी दोषी नहीं हो सकती है, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। जहाँ तक वे जानते हैं, दर्दनाक तथ्य संक्षेप में बताए गए हैं। 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक 31 वर्षीय महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। 36 घंटे की कामकाजी शिफ्ट और बिना ब्रेक के अध्ययन सत्र से थककर वह सेमिनार रूम में एक मंच पर सो गई थी। अगली सुबह प्रशिक्षुओं और साथी प्रशिक्षुओं ने उसकी लाश, अर्ध–नग्न और चोटों के साथ देखी। उसका लैपटॉप, नोटबुक और मोबाइल फोन उसके पास पड़ा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंपने से पहले तथ्यों की रिपोर्टिंग में देरी, अधिकारियों और साथ ही पीड़ित के पिता को दिए गए विरोधाभासी बयानों और सबूतों को दबाने जैसी बातों पर तीखी टिप्पणी की। 1886 में स्थापित और ब्रिटिश औपनिवेशिक दिग्गज के नाम पर स्वतंत्रता तक कारमाइकल मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाने वाला यह अस्पताल डॉ. बिधान चंद्र रॉय से निकटता से जुड़ा था, जो एक प्रख्यात चिकित्सक थे और 1948 से 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। हालांकि, हाल के वर्षों में, आर.जी. कर अस्पताल – हमारी औपनिवेशिक विरासत के बहुत से अन्य अस्पतालों की तरह – ने भी अच्छी प्रतिष्ठा हासिल नहीं की है। स्वच्छता और सफाई के बारे में बहुत कम चिंता की बात है। नर्सिंग सिस्टर्स को खराब तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। पैसे, रिश्वत और खरीदे गए उपकरणों के बारे में संदेह है। शौचालय और सुरक्षित पेयजल मिलना मुश्किल है। अत्यधिक भीड़भाड़ और सरकार की इस धारणा के कारण कि लोगों को वापस भेजना खराब पीआर है, मरीज बिल्लियों के बीच फर्श पर लेट जाते हैं, जो इलाज के कथित स्थान पर बीमारी को और फैलाते हैं। "एक कमरे में 30 बिस्तर हैं", एक नए–नए आए डॉक्टर ने कहा, "तो आपको वहाँ कम से कम 10 बिल्लियाँ मिलेंगी।" सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कॉलेज के शीर्ष अधिकारियों द्वारा लावारिस शवों को बेचने और बायोमेडिकल कचरे की तस्करी की लगातार अफवाहें फैल रही हैं। अस्पताल के बिस्तरों और कॉलेज की सीटों की मांग इतनी अधिक है और आपूर्ति इतनी सीमित है कि नुकसान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिन्हें नौकरी या इलाज की जरूरत है, वे आज के भारत में परेशान नहीं हो सकते। स्वतंत्र सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अनुमान है कि बेरोजगारी 9.2 प्रतिशत है, कम–रोजगार और व्यापक रूप से छिपी हुई बेरोजगारी की तो बात ही छोड़िए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व महासचिव डॉ. अमित मित्रा, जो अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के वित्त मामलों के विशेष सलाहकार हैं, कहते हैं कि 20–24 आयु वर्ग के 44 प्रतिशत से अधिक भारतीय बिना नौकरी के हैं। उनका गंभीर फैसला यह है कि "450 मिलियन भारतीय काम नहीं कर रहे हैं या उन्होंने नौकरी की तलाश छोड़ दी है"। बलात्कार–हत्या के बारे में भले ही पुख्ता तथ्य कम हों, लेकिन मैं स्थानीय मीडिया में अश्लील विवरणों की भरमार देखकर हैरान हूँ, खासकर संजय रॉय नामक एक व्यक्ति के बारे में, जो एक नागरिक स्वयंसेवक है, जिस पर जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और महिलाओं को डराने–धमकाने का आरोप है, लेकिन कभी उसे सजा नहीं मिली, जो अब इस अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। हमें पता चला है कि रॉय, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली था, कोलकाता पुलिस की टी–शर्ट पहनता था, पुलिस स्टिकर वाली बाइक चलाता था और पुलिस बैरक में आराम करता था। कुछ रिपोर्ट में हाल ही में एक मनो विश्लेषणात्मक प्रोफाइल का उल्लेख है जो दर्शाता है कि वह पोर्नोग्राफी का आदी था (पुलिस को उसके मोबाइल में बड़ी मात्रा में पोर्नोग्राफी मिली थी), उसमें "पशु जैसी प्रवृत्ति" थी और उसने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। सीसीटीवी फुटेज में रॉय को 8 अगस्त की दोपहर को जींस और टी–शर्ट पहने हुए अस्पताल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था, उसके पास एक हेलमेट था जो उल्लेखनीय रूप से पुलिस की वर्दी के हेलमेट जैसा दिखता था, और फिर एक अगली सुबह करीब 4 बजे। कुछ रिपोर्टर्स का दावा है कि वह नशे में था और उसने एक अनजान महिला से उसकी नग्न तस्वीर मांगी।

छत्रपति प्रतिमा का ढहना शासन–तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण

ललित

मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष, प्रथम हिन्दू नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गयी 35 फीट ऊंची प्रतिमा का थरथरा कर गिर जाना राष्ट्रीय शर्म एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार का दुःखद अध्याय है। इस तरह हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी इस प्रतिमा का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृत–काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में जिस तीव्रता से व्याप्त है, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है, जो सरकार की साख को धुंधला रही है, यह घटना भारतीय नौसेना की साख को भी बट्टा लगा रही है, यह घटना इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कलई खुल गई है। गौर कीजिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था। सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा के गिर जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है, इससे लोगों का आहत होना भी उचित है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महानायक एवं जन–जन की आस्था के केन्द्र हैं। वे महाराष्ट्र के जीवन का अभिन्न अंग हैं एवं वहां की राजनीति उनके नाम के इर्द–गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र ही नहीं सम्पूर्ण देश में शिवाजी महाराज के प्रशंसक हैं। मराठों के अस्तित्व एवं अस्मिता के वे प्राण रहे हैं, मराठों को उन्होंने ने ही लड़ना सिखाया, उनके जीवन को उन्नत बनाया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महाराष्ट्र की सभी जातियों को एक भगवा झंडे के नीचे एकत्रित किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य–शासन में मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। महाराष्ट्र क्योंकि उनकी जन्मस्थली ही नहीं कर्मस्थली भी रहा इसलिए महाराष्ट्र की आबोहवा में वे आज भी जीवंत हैं। ऐसे महानायक की प्रतिमा के गिर जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने तैयार किया था। कहा तो यही जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण प्रतिमा टूटकर गिर गई।

छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र और मराठा संस्कृति के ही नहीं, बल्कि भारतीयता के प्रतीक एवं प्रेरणा पुरुष हैं। आम मराठी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है। ऐसे में, इस मूर्ति का ढहना राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार एवं भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चार महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने के कारण यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनना निश्चित है। एक मजबूत विपक्षी पार्टी शिव सेना की पूरी राजनीति शिवाजी के शौर्य व आत्म–गौरव से प्रेरित है, एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था और इस काम में गुणवत्ता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। प्रतिमा का ढह जाना छत्रपति शिवाजी का अपमान तो है ही और यह जाहिर है कि इसका काम घटिया गुणवत्ता का था। इसीलिये घटना को शिवाजी के अपमान के रूप में पेश किया जाने लगा है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवाजी की प्रतिमा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस मुद्दे को वोट जुटाने के लिए असरदार हथियार के रूप में जरूर इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन मूल प्रश्न है ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कब सार्थक प्रयास होंगे?

राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि न सिर्फ विपक्ष के आरोपों की धार को निस्तेज किया जा सके, बल्कि सार्वजनिक निर्माण में किसी किस्म की लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों को भी यह संदेश मिल सके कि वे बख्शे नहीं जाएंगे। यह पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी बड़ी निर्माण योजना की कमी इस तरह की भ्रष्ट एवं लापरवाही के रूप में उजागर हुई है। हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बार–बार तार–तार होती रही है। मई 2023 में उज्जैन के महालोक कोरिडोर में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां भी इसी तरह आंधी–तूफान में धराशायी हो गई थीं। अयोध्या में भी सड़के ध्वस्त हो गयी थी। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे–बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं हैरान करने के साथ–साथ चिंतित करने वाली बनी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल–1 पर छत गिरने की घटना से भी हर कोई हैरान हुआ है। मुंबई में घाटकोपर का होर्डिंग गिरना 14 लोगों की मौत का कारण बना था। कहीं नई बनी सड़कें धंस हो जाती हैं तो कहीं नई सरकारी इमारतों में दरारें पड़ जाती है। इन मूर्तियों, पुलों, सड़कों एवं सार्वजनिक निर्माण के अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चरमरा गई है।

उपचुनावों को लेकर सीएम योगी की रणनीति

अजय

उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को पूरी तरह सक्रिय कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में बड़े झटके का सामना करना पड़ा था, जिससे अब ये उपचुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से लगातार अलग–अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए जीत की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को साधने और विकास परियोजनाओं के जरिए जनता की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है, ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में मीरापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवां और सीसामऊ जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें से नौ सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई, जबकि सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजा होने के कारण खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से तीन सीटें जीती थीं, जबकि पांच सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं। शेष दो सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के विधायक काबिज थे। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव सिर्फ अपनी तीन सीटों को बचाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सपा के दबदबे वाली सीटों पर विजय हासिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने का अवसर भी हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छह सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी अभियान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने खुद मैदान में उतरकर सियासी माहौल बनाने का मिशन शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू किया। अंबेडकर नगर से इस अभियान की शुरुआत हुई और इसके बाद अयोध्या, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। हर जिले में पांच हजार से लेकर 17 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई है।

योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाले उन जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, योगी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने लाभार्थीपरक योजनाओं के प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट्स वितरित किए हैं। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी ने उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी के लिए मजबूत आधार तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

बीजेपी की रणनीति में विकास, रोजगार और संवाद को मुख्य हथियार बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को युवाओं की बेरोजगारी को लेकर मिली नाराजगी का सामना करना पड़ा था, जो पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण बना।

इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को साधने की कोशिश की है। इन मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी ने अपनी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ताकि बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में उपचुनाव वाली सीटों के नेताओं के साथ बैठकें कीं और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने न केवल राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि शासन स्तर पर भी तैयारी की है, जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके।

आरक्षण खत्म करने की बात कौन करेगा ?

अशोक

दलित और पिछड़े युवाओं के उत्थान के लिए लाया गया आरक्षण अब सत्ता में पंहुचने माध्यम बनता जा रहा है। अलग.अलग राज्य में राजनैतिक दल जहां आरक्षण को अपने हिसाब से अदल.बदल रहे हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की कोशिश हो रही है। कुछ राज्यों ने अपने यहां ये आरक्षण लागू किया पर वहां के हाईकोर्ट ने उसे अवैध बताते हुए रोक लगा दी, पर ये कोशिश जगहदूजगह जारी है। सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायधीश की संविधान पीठ आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने की बात की तो विपक्ष ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर चुके हैं कि आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू नहीं होगा, इसके बावजूद आरक्षण समर्थक राजनैतिक दलों ने इसके विरूद्ध आंदोलनरत हैं। अभी वे भारत बंद का आह्वान कर ही चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में प्राइवेट नौकरी में स्थानीय के लिए शत प्रतिशत आरक्षण को लागू करने पर खड़ा हो गया। हालांकि प्रदेश कैबिनेट ने पास किया गया ये कानून विरोध को देखते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पर खत्म नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर फिर विचार होगा। हाल के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के आतेदुआते प्रचार आरक्षण पर आकर सिमट गया। भाजपा नेता अपने भाषणों में दावा कर रहे है कि हम देश में मुस्लिम आरक्षण लागू नही होने देंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में मुस्लिम आरक्षण पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही इंडिया गठबंधन दलित और पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे देगा। वे देश का विभाजन करवा देंगे। इस पर कुछ बड़े नेता तो चुप्पी साधे है किंतु समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक बयान में कहा है कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। आजादी के बाद दलित समाज को विकास की धारा में शामिल करने के लिए दस साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज ये आरक्षण राजनेताओं को सत्ता में पंहुचने का माध्यम नजर आने लगा है, वे इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। खत्म करने की नहीं। किसी को यह सोचने की फुरसत नही कि आरक्षण की मार से बचने के लिए देश के प्रतिभाशाली युवा आज विदेशों में जाकर शिक्षा ले रहे है। शिक्षा पूरी कर वहीं नौकरी या व्यवसाय कर चुने गए देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। भारत के बाहरर जाकर बसी भारत की मेधा से प्रभावित होते देश के विकास पर किसी को सोचने का समय नहीं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूटर्न ले लिया है। सरकार ने पहले सी और डी कैटेगरी की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी। फिलहाल, आरक्षण के उस फैसले पर रोक लगा दी गई है। कैबिनेट ने फैसला स्थगित कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ लोगों को 100 फीसदी आरक्षण देने को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने कहा, हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध होने पर इस पर रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि इस बिल पर हम पुनर्विचार करेंगी। देश में यह पहला ऐसा मामला नहीं है। कर्नाटक से पहले प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश और हरियाणा में कोशिश की गई थी. वहीं, मध्य प्रदेश में भी सरकार ने ऐसा ही वादा किया था, लेकिन यह कोशिश रंग नहीं ला पाई थी। 2019 में आंध्र प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई कानून बना था जहां 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी।

पर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था।

फिलहाल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना–कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 80 प्रतिशत नौकरियां देने का प्रस्ताव लाया गया था। सरकार सरकार इसे विधानसभा में भी लाना चाहती थी। लेकिन इसे लाया नहीं गया। कर्नाटक में कई बार प्राइवेट जॉब में कन्नड़ों के लिए आरक्षण तय करने की कोशिश हो चुकी है। सिद्धारमैया सरकार में ये तीसरी बार है जब ऐसी कोशिश हो रही है। इससे पहले 2014 और 2017 में भी सरकार कोशिश कर चुकी है। वहीं अक्टूबर 2020 में येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में ग्रुप सी और डी में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीयों को देने का ऐलान किया था। हालांकि, ये लागू नहीं हो सका था। हरियाणा में 2020 में तब की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून पास किया था। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस कानून को रद्द कर दिया। झारखंड में दिसंबर 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी नौकरियों की ग्रुप तीन और चार में स्थानीयों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के मकसद से बिल पास किया था। ये बिल विधान सभा में पास हो गया था, लेकिन गवर्नर ने इसे लौटा दिया था। आज के हालात का निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक दल आरक्षण की सीढ़ी से सत्ता में पंहुचने के प्रयास में लगा है।

लायंस क्लब जौनपुर क्षितिज का पांचवां स्थापना दिवस समारोह संपन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लायंस क्लब जौनपुर क्षितिज का पांचवां स्थापना दिवस समारोह संस्थाध्यक्ष लायन प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में शहर के होटल में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत रिंकी श्रीवास्तव द्वारा ध्वज वंदना से की गई संस्था के संस्थापक अध्यक्ष लायन शशांक सिंह रानू, पूर्व अध्यक्ष दिलीप सिंह, जय कृष्ण साहू, विष्णु सहाय व निवर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र सेठ, सचिव अजीत सोनकर, कोषाध्यक्ष दीपक साहू व अन्य चार्टर सदस्यों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर की गई।

इस कार्यक्रम मे कई प्रकार के मनोरंजक गेम पूर्व चेयरपर्सन अर्चना सिंह के द्वारा कराकर सभी विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया । संस्था द्वारा सभी चार्टर सदस्यों का अंगवस्त्रम व माला पहनाकर तथा गिफ्ट देकर सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शशांक सिंह रानू ने संस्था की स्थापना कैसे हुई इस सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व अध्यक्ष लायन दिलीप सिंह ने अपने कार्यकाल में किए गए विशाल मेडिकल मेगा कैंप की चर्चा करते हुए संस्था से सम्बंधित अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया तथा सभी लायन व लॉयनेस सदस्यों से नए अध्यक्ष को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिलाया, जिससे संस्था अपने सेवा कार्यों से मण्डल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके।

पूर्व अध्यक्ष लायन जय कृष्ण साहू ने अपने कार्यकाल में किए गए हिंदू नव वर्ष में डांडिया महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई इस पर प्रकाश डाला। पूर्व अध्यक्ष विष्णु सहाय ने अपने कार्यकाल में किए गए बृहद बिजनेस एक्सपो के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह जौनपुर में सबसे बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था और यह प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है। निवर्तमान अध्यक्ष लायन धर्मेंद्र सेठ ने अपने कार्यकाल में किए गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन नवदुर्गा मंदिर सद्भावना पुल पर किए गए बृहद प्रसाद वितरण का जिक्र किया।

उसके पश्चात कार्यक्रम में सभी लोगों ने उत्साह के साथ संस्था की पांचवी वर्षगांठ सेलिब्रेट किया। अन्त में कार्यक्रम संयोजक लायन संजय बैंकर और लायन अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने आये हुए सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम मे कोषाध्यक्ष लायन दीपक साहू व सहकोषाध्यक्ष संजय जयसवाल द्वारा सदस्यों को गुड पे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संस्था में विशेष सहयोग के लिए लायन सुनील कनौजिया जी को संस्थापक अध्यक्ष द्वारा प्राउड मेंबर पिन से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में उपाध्यक्ष अतुल सिंह, सर्वेश जायसवाल, देवआनंद, सुनील जायसवाल, अभिषेक गुप्ता, नीरज कुमार सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव और अंजनी प्रजापति, विशाल बरनवाल, अनिल गुप्ता, वैभव श्रीवास्तव, डॉ सतीश चंद्र मौर्य, देवेंद्र सिंह पिंकू, संजय गुप्ता, डॉ प्रशांत द्विवेदी, डॉ चंदन नाथ गुप्ता, हाफिज शाह,जगदीश चंद्र मौर्य शगप्पूश, राजीव गुप्ता, जगन्नाथ मोदनवाल, दिलीप जायसवाल, रत्नेश जी, रामकृपाल जायसवाल, डॉ दिनेश कनौजिया, सौरभ चौधरी, यवनिका सिंह, चेतना साहू, सीमा सहाय, किरण सेठ, नीतू सिंह, ज्योति जायसवाल, सुषमा सोनकर, चांदनी साहू, मृदुला सिंह, रेखा सिंह, आराधना सिंह, सीमा चक्रवाल, एकता बरनवाल, शिल्पी श्रीवास्तव, डॉ आकांक्षा द्विवेदी, गायत्री जायसवाल, सुधा बैंकर, ऊषा मोदनवाल, रिंकी श्रीवास्तव, निशा कनौजिया, नीलम जायसवाल, बबीता जायसवाल, शिल्पी जायसवाल, नीतू गुप्ता, मीना गुप्ता, मालती मौर्य, उमा गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन लायन अजीत सोनकर, संजय गुप्ता व अर्चना सिंह द्वारा किया गया।

न्यायालय के आदेश पर छह के खिलाफ जानलेवा हमला व एससीएसटी का केस दर्ज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र अंतर्गत कानामऊ गांव में छह माह पूर्व भूमि विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन महिला सहित छह आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमला, दलित उत्पीड़न,घर में घुसकर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। गांव निवासी सीमा पासवान ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि भूमि विवाद को लेकर गत 5 मार्च को पड़ोसी दूधनाथ सिंह इनके पुत्र सुजीत सिंह, विपिन सिंह, पुत्री नीलम,पत्नी प्रेमा देवी वधभयहू नीलम एकजुट होकर उसके घर पहुंच पशुओं को खाने के लिए रखी हौदी जबरन हटाने लगे। विरोध करने पर उक्त लोग मुझे लाठी डंडा और फावड़ा से मारने लगे। बचाव को आई सीमा,संगीता, विनीता और गुड़िया को भी पीटकर कर घायल कर दिया। संगीता को गंभीर चोटें आईं थीं। उन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय के बाद मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में भर्ती कराया गया था। आरोप लगाया की आरोपित राजनैतिक पकड़ वाला होने के चलते थाने पर कार्रवाई नहीं की गई। विवशध होकर प्रार्थिनी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।

डीजीपी ने किया परीक्षा केन्द्र का औचक निरीक्षण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आज दिनाँक 31/08/2024 को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री प्रशान्त कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रही आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत राम भरोसे मैकू लाल इंटर कालेज, तेलीबाग लखनऊ स्थित परीक्षा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया तथा परीक्षा को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

राबर्ट, निराला पीटर सहित एक दर्जन घोड़े बढ़ा रहे हैं अश्वशाला की शोभा

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। पुलिस लाइन स्थित अश्वशाला में रह रहे राबर्ट, निराला, दक्ष, निडर सहित एक दर्जन घोड़े पुलिस लाइन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें कुछ घोड़े तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। जिनकी कुछ ही दिनों नीलामी में हो सकती है। वही बाकी यहां पर यह रहे घोड़े अपनी फुर्ती के साथ–साथ एक से बढ़कर एक करतब भी बीच बीच–बीच में दिखाते हैं।यह जानकारी प्रभारी अश्वशाला राम नाथ गौतम ने दिया।उन्होंने बताया कि इस समय पुलिस लाइन स्थित अश्वशाला में महताब, पन्ना व सूरज नाम का घोड़ा वर्ष 2008,निराला व दक्ष वर्ष 2010,पीटर वर्ष 2012,राक स्टार वर्ष 2013, राबर्ट,चेतक व बहादुर वर्ष 2014, निडर व तेज वर्ष 2015 से अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं।उन्होंने बताया कि इस समय अश्वशाला में सबसे जवान निडर व राबर्ट तथा सबसे बुजुर्ग महताब नामक घोड़ा है। इसमें राबर्ट, निराला, निडर व तेज नामक घोड़े ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाकर

पुलिस लाइन स्थित अश्वशाला का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि इन घोड़ों का उपयोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला,माघ मेला,राम नगरी में आयोजित विभिन्न पर्वों, स्नानों व शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीच–बीच में किया जाता है।वही इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर ये अपने हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि इस अश्वशाला में अधिक से अधिक बीस वर्ष तक घोड़ों की सेवाएं ली जाती है।उसके बाद इन घोड़ों की उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नीलामी कर दिया जाता है।बताते चलें कि इस अश्वशाला विभाग में प्रभारी अश्वशाला राम नाथ गौतम के अलावा एक हेड कांस्टेबल व चार और कांस्टेबल तैनात है। उन्होंने बताया कि यहां पर मौजूद सभी घोड़ों की देखभाल मे किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाती।गर्मी के दिनों उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए कूलर व पंखों लगे हैं।वही अश्वशाला में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।इसके अलावा सभी घोड़ों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

शीघ्र ही राम नगरी में गौशाला व गुरुकुल के अलावा बनेगा विशाल शिव मंदिर – मनोज श्रीवास्तव

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। दूर दराज से राम नगरी मे प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन करने के साथ साथ शिव जी का भी दर्शन पूजन करेगे।जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक साथ राम जी के साथ साथ शिव जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होंगा।यह बातें भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कही।उन्होंने बताया कि आज से नहीं बल्कि इसके पहले भी उनका संगठन मथुरा,वाराणसी,पंपापुर सहित अन्यध धार्मिक स्थलों पर की ऐसे कार्य किये है जिससे वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिल रही है।इसी तरह से भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन इससे पहले राम मंदिर निर्माण मे लाखों रुपए दान स्वरूप दे चुका है।इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा शीघ्र ही राम नगरी में विशाल शिव शंकर जी का मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है।इसके साथ–साथ गायों की संरक्षण के विशाल गौशाला व बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिये गुरुकुल का निर्माण भी कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम के आराध्य शिव जी थे।इसलिए वहां पर राम मंदिर के साथ–साथ शिव जी का भी मंदिर होना चाहिए।

इसी के चलते भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन शीघ्र ही जिले में विशाल शिव जी के मंदिर के निर्माण के साथ–साथ गौशाला व गुरुकुल का भी निर्माण करने जा रहा है।जिससे यहां पर राम भक्त भगवान श्री राम का दर्शन पूजन करने के बाद शिव जी का भी दर्शन पूजन कर सके। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण कार्य के लिये भूमि का अनुबंध भी हो गया है।

'नाली एवं नालों पर किये गये अतिक्रमण को बल पूर्वक हटा दिया जायेगा – मंगला प्रसाद सिंह'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि नगर को साफ–सुधरा एवं अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए 01 सितम्बर 2024 से चिहिन्त सड़कों से अतिक्रमण अभियान चलाया जायेगा और सड़क के दोनों ओर नाली एवं नालों पर किये गये अतिक्रमण को नामित सदस्यों तथा पुलिस की उपस्थित में बल पूर्वक हटा दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि नगर के व्यापारी एवं अन्य दुकानदार जिन्होंने मुख्य मार्गों की सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है वह 31 अगस्त 2024 तक हर–हाल में स्वयं अतिक्रमण हटा लें अन्यथा 01 सितम्बर 2024 से चलने वाले अतिक्रमण अभियान के तहत समस्त अतिक्रमण हटा दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि नगर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने आदि की कार्यवाही के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें नगर मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष तथा पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस निरीक्षक यातायात, सहायक अवसर अभियन्ता विद्युत, सहायक अभियंता एनएचएआई, सहायक अभियंता लोनिवि तथा अधिशासी अभियंता को सदस्य बनाया गया है। डीएम ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिये है कि 01 सितम्बर 2024 से चलाये जाने वाले अतिक्रमण अभियान के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही फोटो सहित प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

हिमालयन पब्लिक स्कूल तथा एंजेल पब्लिक स्कूल विजेता बने

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के मैदान में जिला खो खो संघ हरिद्वार द्वारा अंडर 14 जिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरिद्वार के लगभग 30 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान सिविल लाइन कोतवाली रुड़की के प्रभारी थाना अध्यक्ष आरके सकलानी, आनंद स्वरूप सरस्वती स्कूल के कोच नीरज,हरिद्वार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमके गुप्ता तथा ओलंपिक चौंपियन जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के कोच एवं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पंचकूला नसीम अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी तथा विजेता टीम को मेडल तथा सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रतियोगिता के दौरान जिला खो खो संघ के अध्यक्ष डॉ रजनीश सैनी ने मुख्य अतिथि को इस स्मृति चिन्ह लेकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के दौरान बालक वर्ग में हिमालयन पब्लिक स्कूल रुड़की प्रथम स्थान पर द्वितीय स्थान कौशिक पब्लिक स्कूल इमला इमली खेड़ा तथा तृतीय स्थान मोड फोल्ड पब्लिक स्कूल रहे। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान एंजेल पब्लिक स्कूल बहादराबाद, द्वितीय स्थान द्वितीय स्थान नेचर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रुड़की एवं संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल हरिद्वार तथा सरस्वती पब्लिक स्कूल बहादराबाद रही। जिला हरिद्वार खो खो संघ के सचिव चौंपियन सूरज रोड ने बताया हरिद्वार जिले से चयनित खिलाड़ी नैनीताल में होने वाली राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता मे भाग लेंगे।

प्रतियोगिता के अंत में जिला खो खो संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सैनी तथा सचिव चौंपियन सूरज रोड ने खेल प्रेमियों खेल प्रेमियों, प्रतिभागी खिलाड़ियों तथा सहयोगियों का आभार प्रकट किया।

स्टडी हॉल ने करियर फेस्ट 2024 का आयोजन किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। स्टडी हॉल स्कूल ने हाल ही में करियर फेस्ट 2024 का आयोजन किया, जिसमें 7 प्रतिष्ठित स्कूलों के 700 से अधिक छात्र–छात्रों ने भाग लिया। IDP, प्रथाम, प्रिंसटन रिव्यू, प्लायमाउथ मोजरान, CCA, प्रेप गुरु, UPES, IIAD, और CLAT पॉसिबल जैसे संगठनों के पेशेवर करियर काउंसलर ने छात्रों को विभिन्न निजी और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की। काउंसलरों ने छात्रों को फीस माफी, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक और अतिरिक्त गतिविधियों की आवश्यकताओं, और लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन लिखने के बारे में मार्गदर्शन किया। IDP से काउंसलर प्रियंका चोपड़ा ने कहा, हमारा लक्ष्य छात्रों को आत्मविश्वास से अपना भविष्य संवारने में मदद करना है। हम यहां कई प्रतिभाशाली छात्रों से मिले हैं जो विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, और हमारे काउंसलर वीजा से सम्बंधित सभी प्रक्रिया के मार्गदर्शन में सहायता करने के लिए तैयार हैं। स्टडी हॉल की छात्रा अनघा रमाडी (कक्षा 12 की छात्रा) ने कहा, काउंसलरों ने मेरे दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और मेरे भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में स्पष्टता दी। एक अन्य छात्र उपलब्धि सचान (कक्षा 10 की छात्रा) ने कहा, मुझे अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में स्पष्ट समझ मिली और काउंसलरों ने मेरी सभी शंकाओं का समाधान किया। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी से यह आयोजन बहुत सफल रहा।

आन्तरिक सुरक्षा तथा समाज को भयमुक्त बनाने के लिए कार्य करेगी आर्य वीर सेना – वीरेन्द्र मिश्र

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आज आर्य वीर पार्टी द्वारा जे सी गेस्ट हाउस निराला नगर के सभागार में आयोजित सभा में आर्य वीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र मिश्र ने लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता तथा समाज सेवी

राघवेन्द्र पाठक को पार्टी के लिए लखनऊ का जिला अध्यक्ष घोषित करते हुए कहा कि आर्य वीर पार्टी जाति और धर्मवाद पर नहीं राष्ट्रवाद पर कार्य करेगी। सम्पूर्ण भारत हमारा परिवार है, हमारी जाति भारतीय है और मानवता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हमारा लक्ष्य 80: निर्बल निर्धन शोषित पीड़ित मजदूर किसान बेरोजगार सहित मध्यम वर्ग के सम्मान सुरक्षा तथा न्याय के लिए संघर्ष करना है। जिनकी सरकार बनाने के लिए तो आवभगत होती है परन्तु सरकार बनने के बाद उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है, फिर सरकार 20: पूंजीपतियों सेठ साहूकारों के इशारे पर कार्य करने लगती है। हम 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके संविदा कर्मियों के नियमितीकरण तथा 10 वर्षों से नजूल की भूमि पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे लोगों को उसी भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। श्री मिश्र ने आगे कहा कि राजनीति व्यापार नहीं देश और समाज सेवा है, विधायकों सांसदों जैसे जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन तथा अनावश्यक भत्ते जनता के घन का दुरुपयोग है, इस पर रोक लगाकर इस धन का जनता की सुविधाओं में सदुपयोग होना चाहिए। श्री मिश्र ने यह भी कहा कि देश को गृहयुद्ध से बचाने के लिए, देशकी आन्तरिक सुरक्षा तथा समाज में अमन शान्ति बनाए रखने के लिए शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्य वीर सेना का गठन किया जाएगा। इस सभा में मुख्य रूप से श्री रमेश प्रकाश राव, एवं जन गौतम जे पी मिश्र, सत्यपाल सिंह फौजी, गिरीश बाजपेई, मुकेश वर्मा, अभिषेक अग्रवाल, शैलेन्द्र गुप्ता, शाहिद अख्तर, अरुण कुमार सिंह, हर्ष राज पाण्डेय, डॉ विनोद अग्रवाल. पत्रकार संजय सक्सेना, राकेश शर्मा, अटल बिहारी शर्मा, रामू राक्का सोनिका मिश्रा, पूनम वर्मा, लक्ष्मी शंकर चौरसिया, रजनी मिश्रा, आरती संस जितेश श्रीवास्तव, जितेन्द्र शर्मा, राम प्रकाश लोधी, नरेन्द्र शर्मा, रंजना सिंह, अस्लाफ अहमद आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्री राज कुमार सिंह की अनुमति से 14 सितम्बर 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत विभाग से सम्बंधित वादों के निस्तारण कराए जाने हेतु जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिला जज द्वारा अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को

सफल बनाया जा सके। उक्त बैठक में अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत सुनील कुमार मिश्र, अपर जिला जज कुसुम लता, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत हेमेन्द्र कुमार तथा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई भूपेंद्र प्रताप व विद्युत विभाग के अधिकारी तथा अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पाली पुलिस ने पत्नी के हत्यारोपी बृजेश को गिरफ्तार कर भेजा जेल

ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली(हरदोई)' थाना क्षेत्र के रहतौरा गांव में डंडे से पीट–पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को पाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोपी पति, पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था, बच्चों ने अपने पिता द्वारा मां की हत्या करने की बात पुलिस को बताई थी। जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

ज्ञात हो कि पाली थाना पुलिस को बीते बुधवार सुबह को सूचना मिली कि रहतौरा गांव में बृजेश पुत्र राम औतार ने अपनी पत्नी विनीता की हत्या कर दी। इसके बाद सीओ अनुज मिश्रा, अपराध निरीक्षक वहीद अहमद, वरिष्ठ उप निरीक्षक वीर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जांच के दौरान विनीता का शव घर में खून से लथपथ पड़ा

हुआ मिला तथा पूजा सामग्री भी घर में पड़ी हुई मिली। तंत्र–मंत्र के चलते हत्या करने की बात पुलिस को पता चली, वहीं मृतका की पुत्री ने पुलिस को बताया कि उसके पिता बृजेश ने ऊपरी चक्कर की बात कह कर उसकी मां की डंडे और फुकनी से पीट–पीटकर हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी बृजेश ने विनीता के हाथ की उंगलियां भी प्लास से दवाईं थी, पत्नी की हत्या के बाद बृजेश फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी पति बृजेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। शुक्रवार को थाने की पुलिस टीम ने आरोपी बृजेश को ग्राम नगरिया में गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र पाण्डेय उप निरीक्षक आशीष त्यागी, हेड कांस्टेबल अनुज कुमार पांडेय, कांस्टेबल मनीष कुमार शामिल रहे।

युवक की पीट पीट कर हत्या, मोहल्ले में तनाव

हरदोई। कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लाठियों और सरियों से पीट–पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने सभासद और उसके पुत्र सहित पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर राजदेव मिश्र के अनुसार शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुलेमानी निवासी आरिफ पुत्र शाहिद ने तहरीर दी है कि उसका भाई उस्मान सुलेमानी के सभासद रतीराम पुत्र भजन के घर के सामने से निकलता था। तो रतिराम और उसके पारिवारीजन उसके भाई को निकलने के लिए मना करते थे।शुक्रवार की देर शाम उसका भाई उस्मान रतीराम के घर के सामने से निकला तो सभासद रतीराम उसके पुत्र रोहित ने उस्मान को उधर से निकलने के लिए मना किया। जिस पर उस्मान ने कहा कि वह निकलेगा। इसी बात पर नाराज होकर रतीराम उसके पुत्र रोहित, चौधरी पुत्र सुमेर, ईश्वर पुत्र संतराम, राहुल पुत्र सर्वेश ने लाठियों, डंडों और सरियों से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में घायल उस्मान को परिवारीजन सीएचसी, शाहाबाद ले गए। जहां डॉक्टरों ने उस्मान को मृत घोषित कर दिया। दो दिन पहले भी दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था।तब उस्मान का धारा 151 में पुलिस ने चालान भी किया गया था।आज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री टी वी मुक्त ग्राम पंचायत की श्रृंखला में ग्राम पंचायत असगरपुर एवं परियल में स्वास्थ्य शिविर आयोजित – डा प्रवीण दीक्षित

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना) प्रधानमंत्री टी वी मुक्त ग्राम पंचायत की श्रृंखला में आज ग्राम पंचायत असगरपुर में टी वी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पोर्टेबल एक्स रे मशीन से कुल 64 संभावित टी वी मरीजों के एक्स रे किए गए तथा 64 स्पुटम सैंपल जमा किए गए। गांव वालों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। स्वास्थ्य परीक्षण कर 160 लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई गईं। इस शिविर में सी एच सी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ प्रवीण कुमार दीक्षित, डॉ सर्वेश, सर्वेयर अवधेश, ललित, जावेद एवं ए एन एम शिखा आदि ने विशेष योगदान दिया। इससे पूर्व परियल ग्राम पंचायत में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा टी वी अलर्ट संस्था के सहयोग से टी वी मुक्त ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। डॉ पवन यादव द्वारा 80 रोगियों को देखा गया तथा उन्हें दवा उपलब्ध कराई गई। शिविर में पोर्टेबल एक्स रे मशीन से कुल 67 संभावित टी वी मरीजों के एक्स रे किए गए तथा 67 स्पुटम सैंपल जमा किए गए। यहाँ सी एच सी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ प्रवीण कुमार दीक्षित, डॉ पवन यादव, सर्वेयर अवधेश, रोहित, जावेद एवं ए एन एम सुषमा देवी आदि ने योगदान दिया।

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारी से 97 लाख ठगे

शामली, संवाददाता। जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का धंधा जोरों पर है। ऊन क्षेत्र के गुड़ व्यापारी कृष्णपाल से साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर 97 लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने साइबर सेल से मामले की शिकायत की है। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं झिंझाना के सिकंदरपुर के एक अन्य व्यापारी से भी आठ लाख की ठगी कर ली गई। साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव भटनागर ने बताया कि ऊन के रहने वाले गुड़ व्यापारी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि उनकी फैक्टरी भी है। कुछ दिन पूर्व ही उनका सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अनजान व्यक्ति से संपर्क हुआ। जिसमें कंपनी के ऑनलाइन ट्रेनिंग का झांसा दिया। कहा कि ट्रेडिंग के बदले उन्हें लगाए गए रुपयों के दोगुने रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने रुपये लगाते हुए अलग अलग तारीखों में अलग अलग खातों में रुपये डाल दिए। शुरू में रिफंड मिलता रहा, मगर बाद में रुपये देने से इनकार कर दिया। अब तक वह 97 लाख रुपये गंवा चुके हैं। पीड़ित ने पुलिस से साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं झिंझाना सिकंदरपुर के रहने वाले कृष्णपाल सिंह ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से अनजान ने उनसे संपर्क किया। वह गुड आदि के व्यापारी है। उनसे 30 मीट्रिक टन गुड की मांग की गई। मांग करने वालों ने खुद को हरियाणा का बताया। एडवांस एक लाख रुपये भी भेज दिए। गुड की डिलीवरी करा दी गई। गुड की कीमत 8 लाख 66 हजार रुपये बैठ रही थी, अब रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। एएसपी संतोष कुमार का कहना है कि मामलों की जांच की जा रही है। लोगों से अपील है कि वह साइबर ठगों से बहकावे में नहीं आए। संशय होने पर पुलिस से सीधे शिकायत करें।

कैसे ठगी को अंजाम देते हैं साइबर ठग

साइबर एक्सपर्ट के अनुसार साइबर ठगों का गिरोह शेयर बाजार के एक्सपर्ट का झांसा देकर लोगों के निवेश के लिए बरगलाते हैं और शुरुआत में उन्हें लाभ होता दिखाते भी हैं।

ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, दो की मौत, दो गंभीर

बांदा, संवाददाता। एक बाइक पर सवार होकर जा रहे चार युवकों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गया। इन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। वहां एक और युवक ने दम तोड़ दिया। दो को कानपुर रेफर किया गया है। अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के आऊ अंगद का पुरवा निवासी लवलेश वर्मा (22), अमर सिंह (20), करन (21) और अजय (20) बुधवार की रात गांव से पड़ोसी की बाइक लेकर अमर की बुआ कल्ली के गांव बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अड़ौली गांव जा रहे थे। बिसंडा थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव के पास रात करीब साढ़े 10 बजे उनकी बाइक में पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। अमर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लवलेश, करन और अजय गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। लवलेश ने गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करन और अजय को कानपुर रेफर कर दिया गया है। बिसंडा थाना इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि बाइक अमर सिंह चला रहा था। अमर हेलमेट नहीं लगाए था। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

बांदा। तेज रफ्तार की वजह से दो जानें गईं। लवलेश वर्मा के बाबा छोटेलाल ने बताया कि लवलेश बाहर रहकर ईंट पाथने का काम करता था। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। दो साल पहले उसकी संगीता से शादी हुई थी। वह गर्भवती है। पिता गुलजारी उर्फ सत्येंद्र प्रकाश मजदूरी करते हैं। दूसरी तरफ अमर सिंह घर का इकलौता पुत्र था। घर में मां सुशीला है। पिता बच्चू मजदूरी करते हैं। बाबा छोटेलाल ने बताया कि चारों युवकों के परिवार आऊ अंगद पुरवा में आसपास ही रहते हैं। बुधवार की शाम अमर सिंह को बुआ कल्ली के यहां मिलने जाना था। उसने गांव के लकी की बाइक ली थी। अमर की बुआ के यहां जाने के लिए लवलेश, करन और अजय भी तैयार हो गए थे। रात में तेज रफ्तार हादसे का सबब बन गई।

जिले में मलेरिया के चार नए केस मिले

शामली, संवाददाता। जिले में डेंगू के साथ मलेरिया का भी खतरा बढ़ गया है। इस महीने मलेरिया के चार नए केस सामने आए है। इस साल में अब तक 15 केस सामने आ चुके हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पिछले साल जिले में मलेरिया के 69 केस मिले थे। बारिश के मौसम में मच्छर पनपने के कारण डेंगू व मलेरिया बुखार का खतरा रहता है। इस महीने बाबरी निवासी महिला में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि डेंगू का एक केस पहले जनवरी में मिल चुका है। इसके साथ ही अगस्त में मलेरिया के चार नए केस मिले हैं। इन्हें मिलाकर इस साल में अब तक मलेरिया के 15 केस सामने आ चुके हैं। जिला मलेरिया अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया अगस्त महीने में 3749 स्लाइड की जांच में चार मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई हैं। इस साल में अब तक बुखार पीड़ित मरीजों की 23287 स्लाइड बनाई गई, जिनमें 15 मरीजों में मलेरिया पाया गया।

12 हजार घरों का भ्रमण, छह जगह मिला लार्वा

मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने व घर–घर जाकर लार्वा की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया हुआ है। पांच अगस्त से शुरू हुए अभियान में अब तक करीब 12 हजार घरों का भ्रमण किया जा चुका है। अरबन क्षेत्र में छह डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर लगाए गए हैं जबकि गांवों में आशाएं घर–घर जाकर लार्वा की जांच कर रही है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया अब तक करीब छह घरों में मलेरिया का लार्वा पाया गया, जिसे तत्काल नष्ट कराया गया।

मेरठ में 354 करोड़ से बनेगी इनर रिंग रोड, शासन ने दी अनुमति

मेरठ, संवाददाता। हापुड़ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने के लिए 45 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड के लिए शासन ने अनुमति दे दी है। इस पर 354 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 288 करोड़ रुपये मुआवजे और 66 करोड़ मार्ग निर्माण पर खर्च होगा। शासन को बजट के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव (लोनिवि) ने रजामंदी दे दी है। 15 सितंबर तक ग्रांट आने की उम्मीद है। इसके बाद जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा। मेरठ महायोजना–2001 में एनएच–58 को मवाना रोड, गढ़ रोड, हापुड़ रोड, दिल्ली रोड से जोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2006 में तैयार हुई महायोजना–2021 में इसकी पैरवी की गई, लेकिन दशकों बाद भी मामला परवान नहीं चढ़ा। अब बीते कुछ सालों से शहर में बिछ रहे हाईवे के जाल और इन्हें जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में गढ़ रोड पर सिसौली के पास इंटरचेंज बनाया जा रहा है और यहां से 12 किमी. लंबी सड़क भावनपुर होते हुए मवाना के सलारपुर में पहुंच रही है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही सलारपुर से एनएच–58 को जोड़ने के लिए भी मार्ग का निर्माण हो रहा है। इसके बावजूद हापुड़ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने पर कोई पहल नहीं हो सकी। जुर्रानपुर रेलवे फाटक पर पिछले 13 साल से रेलवे की ओर से बनाया गया पुल हवा में लटका हुआ है। इसके दोनों ओर जमीन अधिग्रहण कर इनर रिंग रोड तैयार होनी थी। इनर रिंग रोड की कुल लंबाई 34.19 किमी. है। मेडा अफसरों के मुताबिक बाईपास से वेदव्यासपुरी योजना तक 2.4 किमी. मार्ग निर्मित है। वेदव्यासपुरी योजना के बाद रेलवे लाइन से दिल्ली रोड तक 1.2 किमी. मार्ग महायोजना मार्ग नहीं है और मौके पर भी इसका निर्माण नहीं हुआ है। हापुड़ रोड से लोहिया नगर नाले तक 1.96 किमी. भाग में 80 मीटर पर विवाद होने के कारण गढ़ रोड भी हापुड़ रोड से नहीं जुड़ सकी है। हाल ही में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की ओर से विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। इसके तहत मेडा ने जमीन अधिग्रहण के लिए लोक निर्माण विभाग से खर्चा वहन का प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ सड़क निर्माण में आने वाले खर्चे को अपनी बाह्य विकास निधि से वहन करने की भी पेशकश की है।

आदेश हो चुके जारी

354 करोड़ से सड़क बनेगी। मुआवजे पर 288 करोड़ रुपये मुआवजा खर्च लोनिवि वहन करेगा। 66 करोड़ रुपये से 45 मीटर चौड़ी सड़क को लोनिवि को मेडा धनराशि देगा। प्रमुख सचिव लोनिवि के पास भी आदेश पहुंच गए हैं। इनर रिंग रोड शहर की लाइफ लाइन है। इसका निर्माण होने से जाम से राहत मिलेगी। रैपिड के काम के चलते यातायात का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में सर्वे कराया गया है। किसानों को मुआवजे की रकम लोनिवि देगा और सड़क निर्माण का खर्च मेडा उठाएगा।

कालाबाजारी मिलने पर कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट

बांदा, संवाददाता। निरीक्षण में गेहूं, चावल, बाजारा,चीनी की कालाबाजारी पाए जाने पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्ति विभाग के निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 28 अगस्त को दोपहर उन्होंने उचित दर विक्रेता अशोक कुमार के दुकान व गोदाम का औचक निरीक्षण किया। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके साथ ही अगस्त महीने का उठान किया गया राशन खाद्यान्न भी कार्डधारकों को नहीं वितरित किया गया।

पूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार से मांगे गए स्टॉक एवं वितरण संबंधित अभिलेख रजिस्टर भी नहीं उपलब्ध करा सके। दुकान में मौजूद ई–पॉश मशीन का निरीक्षण करने पर कुल 75.40 क्विंटल गेहूं, 184. 25 क्विंटल चावल, 8.08 क्विंटल बाजारा, 1.53 क्विंटल चीनी की कालाबाजारी पाई गई। जिस पर डीएम के अनुमोदन एवं आदेश के बाद पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार अशोक कुमार के खिलाफ गुरुवार को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्ति निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि एसडीएम रावेंद्र सिंह द्वारा 17 अगस्त को कोटेदार के खिलाफ मिली हुई शिकायतों पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कोटेदार के द्वारा जारी की गई नोटिस का कोई जवाब नही दिया गया था।

एसडीएम की छापेमारी में मिली अनियमितता, अल्ट्रासाउंड सेंटर किया सील

सहारनपुर, संवाददाता। सहारनपर जनपद के छुटमलपुर एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कस्बे के देहरादून रोड स्थित नमिशा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर वहां गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेडियोलाजिस्ट और टेक्नीशियन नहीं मिला। डाक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। एसडीएम की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सेंटर को सील कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ नमिशा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचे। टीम के पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। उन्होंने केंद्र संचालक से चिकित्सक और टेक्नीशियन के बारे में पूछा तो वे कोई उत्तर नहीं दे सकी।

जांच के दौरान उन्होंने पाया कि एक महिला द्वारा रोगियों के अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट की इंतजार में बैठे रोगियों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने बताया कि उक्त महिला द्वारा ही उनके अल्ट्रासाउंड किए गए हैं तथा वही रिपोर्ट बना कर दे रही है। एसडीएम की रिपोर्ट पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डा राकेश चंद्रा ने सेंटर को सील करने की प्रक्रिया संपन्न कराई। कोई रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन नहीं मिला। बिना डॉक्टर के ही अल्ट्रासाउंड किए जा रहे थे और डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट जारी की जा रही थी। सेंटर को सील करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी गई है।

मिल चलाने को तीन हजार कर्मियों 400 करोड़ की जरूरत

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में लाल इमली चलेगी तो परेड, सीसामऊ और ग्वालटोली बाजार फिर गुलजार होंगे। जानकारों का कहना है कि मिल चलाने के लिए कम से कम तीन से चार हजार नई भर्तियां करनी होंगी और चार सौ करोड़ के पैकेज की जरूरत होगी। मौजूदा समय में मिल में दो सौ से ज्यादा कर्मचारी और अफसर हैं जो सेवानिवृत्त की उम्र पर खड़े हैं। मिल में स्विटजरलैंड से सालों पहले छह मशीनें आई थीं। जिनकी पैकिंग तक नहीं खुली है। इनके खराब होने का अनुमान है। अंग्रेजी शासन काल 1876 में लाल इमली मिल की नींव रखी गई थी। 26 एकड़ में बनी इस मिल में प्रतिदिन लगभग तीन पाली में 8000 से अधिक श्रमिक काम करते थे। लाल इमली में 1989 से कोई नई भर्ती नहीं हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने लाल इमली के सर्वोच्च गुणवत्ता से प्रभावित होकर पुरस्कार भी दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अपने समय में लाल इमली की कश्मीरी टूश लोई भेंट की गई थी। जिसे वो अपने कंधे पर डाले रहते थे। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निरीक्षण के दौरान लाल इमली से सेनानियों के लिए कंबल मांगे थे। उन कंबलों ने भारत की सीमा पर जंग लड़ रहे सीमा सुरक्षा बल के सेनानियों को काफी राहत पहुंचाई थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री चुनी गई तब 18 जून 1981 को लाल इमली मिल का अधिग्रहण करते हुए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय से संबंधित कर दिया। अपने गजट में कहा था कि लाल इमली मिल को कभी बंद नहीं किया जाए।

पंचम वेतनमान लागू करके भारी भरकम एरियर भी दिया

इस मिल से गरीबों को रोजगार मुहैया किया जाएगा और सस्ती दरों पर उन्हें कंबल दिए जाएंगे। 2002 तक कर्मचारियों को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वेतनमान सोलह आने प्रतिदिन का भुगतान किया जाता था। किसी भी छुट्टी का पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया जाता था। तुलनात्मक अधिकारियों को शासन द्वारा 2011 में पंचम वेतनमान लागू करके भारी भरकम रकम का एरियर भी दिया गया था। श्रमिक संगठनों ने 2002 में वेतन पुनरीक्षण की मांग की थी।

तत्कालीन कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने किया था निरीक्षण

इसके चलते 2005 में मंत्रालय द्वारा बिना अधिकृत किया हुआ वेतनमान लागू किया गया। जिससे मिल के वेतन पैकेज में आर्थिक भार पर बुरा प्रभाव पड़ा और मिल बीमार हो गई। 2009 से उत्पादन कम हो गया। उस समय प्रतिदिन तीन सौ मीटर कपड़ा बनाता था। मिल में स्विटजरलैंड की कंपनी की 12 मशीनें पहले से ही लगी हैं। उनकी स्थिति बेहद खराब है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 13 अक्तूबर 2014 को लाल इमली में पहली बार तत्कालीन कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने लाल इमली का निरीक्षण किया।

मिल चली तो फिर चलने लगेगी ऐतिहासिक घड़ी

लाल इमली मिल की पहचान इसके उत्पादों से थी। मिल में घड़ी लगी है। यह लगी चारों ओर से दिखाई देती है। यहां से निकलने वाले हजारों लोग इसके बजते घंटे की आवाज से समय का अनुमान लगा लेते थे। इस घड़ी में चाबी भरने के लिए चार कर्मचारी लगते थे। हालांकि बीते कई साल से घड़ी भी बंद हो गई है। अब उम्मीद है कि मिल चली तो घड़ी भी चलने लगेगी।

कपड़ा बाजार में बढ़ेगी रौनक

लाल इमली मिल में बनने वाली 60 नंबर लोई, कंबल, ब्लेजर, सूट का कपड़ा, पश्मीना शॉल की बाजार में बहुत अच्छी मांग थी।

शहर के थोक कपड़ा बाजार जनरलगंज, नौघड़ा, काहूकोठी आदि में इनकी मांग रहती थी। यदि मिल चलती है तो शहर के कपड़ा बाजार में फिर से पुराने उत्पाद मिल सकेंगे।

प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में मिली चिकित्सक की लाश

आगरा, संवाददाता। आगरा के बाह थाना क्षेत्र के बटेश्वर स्थित प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में चिकित्सक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में महिला कर्मचारी पहुंची। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यहां से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर में साईं शिक्षण संस्थान का मामला है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में शुक्रवार की सुबह 9.30 बजे चिकित्सक योगेश कुमार(46) का शव पड़ा मिला। मृतक के सिर, गर्दन, पीठ पर चोट के निशान हैं। वारदात की जानकारी तब हुई जब महिला कर्मी सीमा केन्द्र पर पहुंची। उन्होंने केन्द्र पर रहने बाबा से दरवाजा खुलवाया। महिला कर्मी उन्हें देखकर रोने लगी। इसके बाद सीमा ने साथी कर्मी शोभना एवं काम्या को बुलाया। चिकित्सक के छोटे भाई राम प्रकाश मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम छानबीन में जुट गई है। बाबा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एसीपी बाह गौरव सिंह ने बताया छानबीन की जा रही है।

पत्नी निकली कातिल, मोहब्बत में आड़े आया पति तो सुपारी देकर करा दी हत्या

बिजनौर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने रईस हत्याकांड का खुलासा मात्र 24 घंटे के भीतर कर दिया। रईस की पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर पति की सुपारी देकर हत्या कराई। नजीबाबाद के मधुरापुर मोर क्षेत्र में स्टोन क्रेशर के निकट 28 अगस्त की सुबह अधेड़ उम्र व्यक्ति का चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला था। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर पुलिस ने न केवल अज्ञात शव की पहचान की, बल्कि 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। सुल्तानपुर आदमपुर लक्सर निवासी रईस की हत्या उसकी ही पत्नी दिलशाना ने प्रेमी जावेद अली के साथ मिलकर सुपारी देकर कराई। सीओ देश दीपक सिंह थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर ने घटना के 24 घंटे बाद सनसनी खेज हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने मृतक की पत्नी दिलशाना, प्रेमी जावेद अली और किराए के दो हत्यारों कैथल पथरी निवासी अब्दुल वाहिद, और पथरी हरिद्वार निवासी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया। रईस का 20 साल पहले दिलशाना से विवाह हुआ था। निकाह के एक वर्ष बाद से ही जावेद अली जिसका रईस के घर आना जाना था, पत्नी दिलशाना के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पति रईस दिलशाना को बुरी तरह मारता पीटता था और उसका शोषण करता था।

परेशान होकर पत्नी ने प्रेमी जावेद अली संग मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रेमी जावेद अली ने भाड़े के हथियारों से एक लाख रुपये में रईस की हत्या का सौदा किया। 40 हजार रुपये एडवांस दिए शेष 60 हजार बाद में दी जानी थी। हत्यारे ने काम के बहाने से रईस को नजीबाबाद क्षेत्र लाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने रईस की पत्नी सहित चार हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

संक्षिप्त खबरें

आगरा छावनी के सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल

आगरा, संवाददाता। आगरा छावनी के सफाई कर्मचारी शुक्रवार सुबह हड़ताल पर चले गए। इस दौरान छावनी कार्यालय के बाहर बैठकर उनके द्वारा हंगामा किया गया। आरोप है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वे कूड़ा नहीं उठाएंगे। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि विनोद बघेल नाम का एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिसने उनके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं उनसे जाती सूचक शब्द भी बोले। रंगदारी न देने पर नौकरी खाने की धमकी दी। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने विनोद बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी द्वारा सफाई कर्मचारियों को लगातार धमकी दी जा रही है, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी।

यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा देने आया अभ्यर्थी

आगरा, संवाददाता। आगरा में पिनाहट का रहने वाला युवक पुलिस की भर्ती परीक्षा देने अपनी बाइक से अलीगढ़ जा रहा था। थाना ट्रांस यमुना के टेडी बगिया क्षेत्र के पास दबंग फाइनेंस कर्मियों ने युवक को रोक लिया। उसकी बाइक छीन ली। युवक ने जब इसका विरोध किया तो फाइनेंस कर्मी ने मारपीट शुरू कर दी और बाइक लेकर चले गए। बाइक ले जाते हुए दोनों दबंग फाइनेंस कर्मियों का वीडियो युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए देरी होने पर युवक ने बाइक लूटे जाने की सूचना डायल 112 और उच्चाधिकारियों को फोन के माध्यम से दी। मामले की जानकारी होने के बाद फाइनेंस कर्मियों ने को ढूढ़कर युवक को उसकी बाइक वापस दिलाई। इस पर युवक परीक्षा देने अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया। युवक द्वारा थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई है।

युवा कारोबारी की सड़क हादसे में मौत

आगरा, संवाददाता। आगरा के एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब के पास बृहस्पतिवार रात को तेज रफ्तार एक गाड़ी ने स्कूटर से घर लौट रहे युवा कारोबारी की स्कूटर में टक्कर मार दी। हादसे में घायल कारोबारी की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुष्प एनक्लेव लोहा मंडी निवासी सौरभ चोपड़ा बड़ा बाजार में जेवरात की फर्म चलाते थे। परिवार के लोगों ने बताया कि रात तकरीबन 10रू00 बजे अपने दोस्त को भगवान टॉकीज पर छोड़कर घर लौट रहे थे स्पीड कलर लैब कट के सामने जैसे ही उन्होंने स्कूटर को टर्न किया, तभी हरीपर्वत की तरफ से आई तेज रफ्तार एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गई। युवा कारोबारी की मौत से जहां बाजार में शोक दौड़ गया, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक कारोबारी की दो बेटियां हैं।

फर्नीचर फर्म में जी एस टी टीम ने दी दबिश

बांदा, संवाददाता। जीएसटी की टीम ने कस्बा के एक फर्नीचर की दुकान में दबिश दी। टीम ने तीन घंटे तक सभी जरूरी दस्तावेज खंगाले। दुकान मालिक को दो दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।टैक्स चोरी करने की शिकायत मिलने पर जीएसटी टीम ने कस्बे के कालिंजर मार्ग में नहर पुलिया के पास स्थित हार्ड वेयर एंड प्लाईवुड दुकान में गुरुवार को शाम छापा मारा। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार की मौजूदगी में करीब दो घंटे से अधिक समय तक छानबीन की गई। पूछताछ के बाद सभी बिक्री से संबंधित बिल बाउचर कब्जे में लिए। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि दुकान में टैक्स चोरी की शिकायत पर छापा डाला गया है। संचालक ने कुछ कागज दिखाए हैं। कुछ जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए हैं। साथ ही दुकानदार को अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। सभी का मिलान होगा। अगर सही नहीं पाए गए तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद, कर अधिकारी सुमित कुमार सहित टीम के लोग मौजूद रहे।

अवैध तरीके से संचालित क्लीनिक सील, संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

शामली, संवाददाता। कस्बे में बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से संचालित क्लीनिक को एसीएमओ डॉ. विनोद कुमार ने सील कर दिया। इस मामले में क्लीनिक संचालक सादिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीएमओ डॉ. विनोद कुमार ने बृहस्पतिवार को थाने पर दी तहरीर में बताया कि कस्बे की मयूर मार्केट में चौहान लाइफ केयर सेंटर के नाम से क्लीनिक चलाया जा रहा है। संचालक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को मिली शिकायत पर कई दिन पहले क्लीनिक पर पहुंचकर जांच की थी और संचालक सादिक को नोटिस तामील कराते हुए तीन दिन के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर लाइसेंस व अन्य कागज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वत्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।